number of dais to look after the deliveries, ante-natal and postnatal cares in the rural areas. The details of the Scheme including financial implications are under examination of Finance Ministry and Planning Commission.

दिल्ली में लम्बित टेलीफोन बिल

699. श्री के० लकप्पा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में टेलीफोन कनेक्शनों को भारी राशि के बिल का भुगतान न किए जाने के बावजूद काटा नहीं गया है तथा सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है ;

(ख) क्या टेलीफोन संख्या 70695 और 631295 भी ऐसे दो टेलीफोन हैं जिनके विरुद्ध टेलीफोन विभाग से मिलीभगत होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) दिल्ली में करीब 1,30,000 टेलीफोन कनेक्शनों में से केवल 211 ऐसे मामले हैं जिनमें 5000 रुपए या इससे अधिक रकम के बिल बकाया है। और टेलीफोन कनेक्शन काटे नहीं गए हैं।

उनमें से टेलीफोन के 132 मामले ऐसे हैं जिन्हें काटने से छूट दी गई है 5 मामलों में बकाया रकम की अदायगी किश्तों में की जा रही है। शेष 74 मामलों में टेलीफोन के बिल विवादग्रस्त हैं। उनकी जांच की जा रही है।

(ख) और (ग). टेलीफोन नं 70695 तीन बार काटा गया था और तारीख 8-4-1975 को उसे अंतिम रूप से काट दिया गया था। टेलीफोन नम्बर 631295 चौदह बार काटा गया थ और उसे तारीख 3-6 77 को अंतिम रूप से काट दिया गया है।

Recruitment of Local People in Public Sector Undertakings

700. SHRI GANANATH PRADHAN: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Central Government have taken any steps to see that the Public Sector Undertakings such as H.A.L., H.S.L., Fertiliser Corporation of India and Food Corporation of India are complying with the labour laws, which provide that the public sector undertakings should recruit local employees for posts carrying less than Rs. 500.00 per month;

(b) the percentage of such employees in these undertakings in Orissa; and

(c) whether there is any case of retrenchment and malafide punishment by the authorities concerned against the labourers in these undertakings and their number?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) There is no Central law requiring the Central Government Public Sector Undertakings to recruit local persons for posts carrying less than Rs. 500.00 per month. The Bureau of Public Enterprises has issued general insructions to the Chief Executives of all Public Enterprises that they must, to the extent possible, recruit through local employment exchanges, their requirement of staff in respect of posts carrying basic salary of less than Rs. 500.00 per month.

(b) and (c). The requisite information is being collected and will be laid on the table of the Sabha as soon as the same is received.